बर्षः- 06
अंकः- 120
मुरादाबाद
(Friday)
21 August 2026
पृष्ठः-8
मूल्यः- 3.00 रूपया

दैनिक
प्रातः कालीन
क्यूँ न लिखूँ सच
राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र
भारत सरकार से रजिस्टर्ड
RNI No.UPBIL/2021/83001
मुरादाबाद से प्रकाशित
प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

भारत-जापान रक्षा संबंधों को नई गति, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम द्विपक्षीय वार्ता

भारत और जापान, चीन की बढ़ती चुनौती के बीच अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में आज भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने हिंद प्रशांत महासागर में मुक्त परिवहन का समर्थन किया। भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच गुरुवार को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। यहां दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को व्यापक बनाने, समुद्री सुरक्षा साझेदारी को गहरा करने तथा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाने पर चर्चा की। चीन की बढ़ती चुनौती के बीच हो रही बैठक- यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र एवं निर्बाध वैध व्यापार को महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बैठक की शुरुआत में राजनाथ सिंह ने जापानी रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में आवश्यक किसी भी सहायता, राहत या सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत-जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। दोनों देश अगले वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत और जापान की मित्रता दोनों देशों के साथ-साथ व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, लचीलापन और नियम आधारित व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला बन गई है। एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्रों के रूप में भारत और जापान की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।समुद्र में बढ़ रही चुनौती

राजनाथ सिंह ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि भारत और जापान की समुद्री जीवनरेखाएं बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में नौवहन की स्वतंत्रता, हवाई क्षेत्र से निर्बाध आवाजाही और वैध व्यापार को बिना किसी बाधा के जारी रखना केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री ने भारत के %महासागर दृष्टिकोण और जापान की मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत पहल के बीच बेहतर तालमेल को वर्तमान समय में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के दृष्टिकोणों का समन्वय पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकता है। बैठक में दोनों पक्षों के बीच रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है।

खासकर मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों पर विचार किया जा रहा है। भारत-जापान के संबंध हुए हैं मजबूत- गौरतलब है कि भारत और जापान पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग को सैन्य अभ्यासों और उच्चस्तरीय संवाद से आगे बढ़ाकर रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित कर रहे हैं। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच हुई तीसरी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2 प्लस 2 वार्ता में भी मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत तथा द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी।द्विपक्षीय वार्ता से पहले जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त को ही नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उनकी श्रद्धांजलि भारत के वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान का प्रतीक रही।

संक्षिप्त समाचार

टपकती छत, टूटी व्यवस्था और बदहाल स्कूल- अभिजीत दीपके बोले- मंत्रियों के कुत्तों को भी मिलती हैं बेहतर सुविधाएं

अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित परिवहन और स्कूलों में सुरक्षा की कमी पर सरकार को घेरा तथा मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सरकारी स्कूल बेहद दयनीय स्थिति में हैं और कई जगह छात्रों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। दीपके ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि मंत्रियों के कुत्तों को भी इन छात्रों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव- दीपके के नेतृत्व में उनके संगठन ने पिछले सप्ताह 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के तहत उन्होंने लातूर जिले की औसा तहसील के उजनी गांव स्थित जिला परिषद स्कूल का दौरा किया। कक्षाओं, बेंच, शौचालय और सुरक्षित संपर्क सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि कुछ स्कूलों में छात्रों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार जैसी स्थिति बनी हुई है।

वंदे मातरम विवाद: कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति, गृह मंत्री शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला

वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वीएचपी के राष्ट्रीय पवक्ता विनोद बंसल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, कल कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्र-विरोधी फैसला लिया। कांग्रेस ने अपने 1937 के प्रस्ताव के अनुसार वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। अमित शाह ने कहा, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की इस गलती को सुधार दिया है और इसे कानूनी आधार भी दिया है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने न केवल बंकिम (चंद्र चटर्जी) बाबू की इस रचना का अपमान किया है, बल्कि उन लाखों लोगों का भी अपमान किया है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अमित शाह ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी अपने 1937 के प्रस्ताव को लागू कर रही है, लेकिन संसद की ओर से बनाए गए कानून को खारिज कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी हो रही है कि (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष) राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अमित शाह ने कहा, देश ने एक बार वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने की गलती की थी और हमें इसके नतीजे भुगतने पड़े हैं। उन्होंने कहा, अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और कहना चाहिए कि उसकी तुष्टीकरण की राजनीति अब और नहीं चलेगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की निंदा करती है। वीएचपी ने भी कांग्रेस की आलोचना की- वहीं, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। वीएचपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी सोच से चलती है और तुष्टिकरण के बिना टिक नहीं सकती। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाकी चार छंद न गाने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि उनमें ऐसे शब्द हैं, जो भारतीय मूल्यों, प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय भावना से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, बाकी हिस्से में धर्म, मर्मन, शक्ति, भक्ति, मंदिर, वाणी, ज्ञान और दुर्गा जैसे शब्द हैं। ये भारतीय मूल्यों, संस्कृति, प्राचीन परंपराओं, आस्था, विश्वास और राष्ट्रीय भावना से गहराई से जुड़े हैं।बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीतिक सोच भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि पार्टी %विदेशी सोच% से प्रेरणा लेती है और भारतीय परंपराओं से जुड़े शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकती। बाकी चार छंद क्यों नहीं गाए जाएंगे? कांग्रेस कार्य समिति यानी ने बुधवार को वंदे मातरम को लेकर अपने 1937 के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब से कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो अंतरे गाए जाएंगे।

राहुल गांधी का दावा: पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई;कांग्रेस को सलाह दी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन अंतिम दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार पर हमला किया। दोनों नेताओं ने क्या-क्या कहा?लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन %अंतिम दौर% में है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी का सियासी अंत हो चुका है। इनका वक्त खत्म हो गया है। मोदी का शासन आखिरी दौर में है। इनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरी तरह पीछे हटने की स्थिति में बताया। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने को कहा।ये बातें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कही गईं। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश की राजनीतिक स्थिति और अहम मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।खरगे ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। खरगे ने दावा किया कि हाल के वर्षों में 94 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने युवाओं के लिए साफ, व्यापक और तय समय में पूरा होने वाला %शिक्षा से रोजगार रोडमैप% बनाने की मांग की। राम मंदिर के चढ़ावे पर क्या बोले?- खरगे ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले पैसे, सोने और दूसरी चीजों के रूप में मिले चढ़ावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इस चढ़ावे का हिसाब कैसे रखा जा रहा है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खरगे ने कहा कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद सीडब्ल्यूसी की यह पहली बैठक है। इसमें देश से जुड़े कई अहम और तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें युवाओं का भविष्य, राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चढ़ावे का हिसाब और भारत की सीमाओं पर चीन के कथित कब्जे की रिपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं। युवाओं की स्थिति को लेकर भी खरगे ने उठाए सवाल- कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने युवाओं को %गहरी निराशा के दलदल% में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद और रेवड़ी संस्कृति की दौड़ के बीच शिक्षा और रोजगार को नजरअंदाज किया गया है।

लिव-इन रिलेशनशिप: हाईकोर्ट ने कहा- सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी के समान, माता-पिता भी नहीं कर सकते दखल

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सहमति से साथ रह रहे वयस्कों के रिश्ते में माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त दखल नहीं दे सकते। परिवार की धमकियों से परेशान कपल को पुलिस सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने इसे शादी के समान बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्कों का रिश्ता शादी के समान है। माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते और न ही उनकी जान या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। अदालत ने परिवार की ओर से धमकियों का सामना कर रहे एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 13 अगस्त को दंपती की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता दंपती की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे कुछ समय से साथ रह रहे हैं और एक-दूसरे से शादी करने का भी इरादा रखते हैं।अदालत को बताया गया कि लड़की के पिता और भाई इस रिश्ते से खुश नहीं थे और वे लगातार दोनों को हिंसा की धमकी दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी (एसएचओ) से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही- अदालत ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा, सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उनके माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त हों, उनकी पसंद में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने का अधिकार अथवा अधिकारिता नहीं रखता। उन्हें उनकी जान या स्वतंत्रता के लिए धमकी देने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है।% अदालत ने आगे कहा, %याचिकाकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और कानूनी रूप से एक-दूसरे से विवाहित नहीं हैं, लेकिन दोनों सहमति से वयस्क हैं, इसलिए उनका रिश्ता शादी के समान है। - सामाजिक पूर्वाग्रहों से मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते- न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों की शादियों को जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था के आधार पर मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को 'सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों' के आधार पर सीमित करना व्यक्ति की स्वतंत्र पहचान से वंचित करने के समान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवाह न होने के बावजूद वयस्कों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-दूसरे के साथ रहने का असीमित अधिकार है। अदालत ने कहा कि अब कानून की नजर में इस अधिकार को मान्यता प्राप्त है

और विधायिका ने भी इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे प्रावधानों के तहत मान्यता दी है।

संपादकीय Editorial

New Accounts to Increase Revenue

In an effort to increase revenue, the Himachal government has opened several accounts, and as a result, the Dak Bungalows, which were once freeloaders, are now gaining financial respectability. In this context, select rooms in Himachal Bhawan, Sadan, and Circuit Houses have now been put on the new rate burner. If accommodation rates in Circuit House rooms, other than those in Delhi, Chandigarh, and Shimla, change, a carpet that costs twelve hundred rupees will eventually cost four thousand rupees for a night's stay. Although this decision has not yet been included in the list for various reasons, the implementation of this wish will increase the cost of government accommodation. After all, if the allocation of classified rooms from Dak Bungalows to Circuit Houses, and beyond, Himachal Sadan and Bhawan, now falls prey to the lure of new businesses, expectations will also rise. Himachal's Dak Bungalow culture is a culture of prestige, authority, access, and the influence of power, which blossoms from time to time. After carefully evaluating the art of rest house construction within the role of every department in the state, the situation has reached a point where all these properties are becoming unprofitable and fundamentally inefficient. Even if they are accepted as part of the state's hospitality, the current situation will have to be rectified, otherwise, a trend of properties being exploited by one or another influence has begun. The state has nearly two thousand dak bungalows, circuit houses, halls, and buildings, but their management structure is fragmented. Almost every department has built rest houses within its own financial resources or budgetary resources, but no permanent management has been developed for their maintenance. Consequently, rest houses have proven to be merely a wasteful expenditure for departmental performance. Their justification and contribution are shrouded in doubt, so who would consider the uniformity of their operations? While the formal decisions to increase rates will have an impact, the system now needs to be streamlined and streamlined. The term "rest house" dates back to the British period, symbolizing hospitality with abundant evidence of VIP status. This system has become more than just a place to rest overnight; it has become a form of government courtesy, a means of demonstrating influence. At a minimum, the chain of rest houses should be integrated with a system of fiscal discipline, ensuring financial accountability, proper management, and transparent booking. All dak bungalows should be brought under one roof, meaning the number of rooms in a combined rest house should be determined based on the city's status and administrative role. In a city like Hamirpur, if a combined rest house with fifty rooms is built and handed over to the Tourism Corporation, there will be no questions about its appropriateness or criticism of its management. This way, the various dak bungalows scattered throughout the city can be utilized for other purposes or offices. In addition to the Himachal Bhawans and Sadans in Delhi and Chandigarh, dak bungalows with at least fifty to hundred rooms should be operated for the people of Himachal Pradesh under better management. If a complex of at least a hundred rooms were built in a place like Haridwar for Himachali travelers or tourists, the seat of faith would be comfortably laid out through the Tourism Corporation. In such a situation, if the government wants to increase the rent of Himachal's Sadan, Bhawan, and Circuit House, then this could be possible for every rest house based on classification and facilities. Otherwise, even HPTDC hotels are currently lagging behind the competition.

It's time to reduce dependence on the Strait of Hormuz.

India's true strategic independence is possible only when our development is based on indigenous renewable energy rather than the uncertainty of foreign oil. Expanding strategic options and achieving energy self-reliance will pave the way for India's establishment as a decisive power on the global stage. The Strait of Hormuz handles one-third of global oil trade. India must reduce its dependence on the Strait of Hormuz for energy security. The Chabahar port and renewable energy are important options. The Strait of Hormuz, which has become a power battleground between the US and Iran, has raised serious questions about global energy security and the trade system. Nearly one-third of the world's maritime oil trade passes through the narrow Strait of Hormuz. Any tension arising here directly destabilizes global oil and gas prices and supplies. The entire industrial machinery of both developed and developing countries depends on the security of this Strait. Demand for oil and gas is also increasing in India, which is becoming an economic power. If this route is completely disrupted, crude oil prices could surpass $150 per barrel, potentially triggering a global recession. Therefore, reducing India's dependence on the Strait of Hormuz is no longer an option, but an imperative. The Hormuz crisis is a clear message for India that excessive dependence on a single geographical route is dangerous to national security and economic sovereignty. The surge in oil prices will increase India's import bill, exacerbating the current account deficit, further weakening the rupee. The issue is not limited to oil; it also concerns the safety of millions of Indian expatriates living in Gulf countries and the foreign exchange flows from there, which could suddenly decline or even cease in the event of a major military conflict. The Hormuz dispute is a reminder to India that it must diversify its energy and trade routes. Instead of relying on the Strait of Hormuz, India must make serious efforts to develop its own alternative routes and security mechanisms. The Strait of Hormuz is crucial because no existing route can match its capacity (approximately 21 million barrels of oil per day). Saudi Arabia's East-West Pipeline, which connects the Persian Gulf directly to the Red Sea, has a capacity of only five million barrels per day. The United Arab Emirates' (UAE) Dhabi Crude Oil Pipeline bypasses Hormuz and transports oil to the port of Fujairah (Gulf of Oman), but its capacity is also limited to 1.5 million barrels per day. Iraq's Turkish pipeline also does not always operate at full capacity due to technical constraints and regional politics. The Cape of Good Hope route is too long, increasing the time and cost of cargo transportation significantly. Construction of the India-Middle East-Europe Economic Corridor has not even begun. The project is still in the planning and coordination stages. Israel-Hamas tensions have slowed the project's progress. Even all alternatives combined cannot meet the Strait of Hormuz's shortfall by more than 40 percent. Amidst the geopolitical turmoil, India is pursuing a multi-pronged plan to ensure its energy security and strategic autonomy, aiming to reduce energy dependence and establish the country as a global economic power. Iran's Chabahar port is central to this strategy. It provides India direct access to Afghanistan and Central Asia, bypassing Pakistan. By making Chabahar a gateway to the 7,200-km-long International North-South Transport Corridor, India can not only shorten its distance to Russia and Europe but also make its exports more competitive in the global market. Currently, most of India's trade is routed through the Suez Canal, which is lengthy and expensive. This corridor significantly reduces both distance and cost and can strengthen Iran's access to Central Asia's energy resources. To this end, India can provide technical and financial assistance to Iran to expedite the completion of the Chabahar-Zahedan rail link. The Chabahar-Zahedan rail project is approximately 628 km long. Along with rail connectivity, this port could prove to be a game-changer for India. As a new energy security option, India is also working on a deep-sea gas pipeline to Oman. This pipeline not only bypasses the Strait of Hormuz but also Pakistan. Being deep under the sea, the pipeline will be relatively safe from war or maritime tensions and will provide a source of uninterrupted energy supply for India. To become an economic superpower, India must also emphasize internal reforms. Self-reliance in the National Green Hydrogen Mission, solar, and wind energy will completely free us from the trap of global instability. India's true strategic independence is possible only when our development is based on indigenous renewable energy rather than the uncertainty of foreign oil. Expanding strategic options and achieving self-reliance in energy will pave the way for India to establish itself as a decisive power on the global stage.

Railways on the Path to Modernization

Rail and weld breakage incidents have been reduced by 90 percent, and approximately 1,800 track machines are operational. The Railways has also launched a new online system, called the Track Management System (TMS). 55,000 km of tracks have been renovated, improving safety. Advanced inspections have reduced rail breakage incidents by 90%. Track speeds exceeding 110 km/h have been reduced by 80%. More than 25,000 trains run daily in India. These trains carry over 20 million passengers daily and transport large quantities of coal, iron ore, grain, steel, cement, and other commodities across a rail network of over 137,000 km. The foundation of this system is the rail track. When the track is in good condition, trains can safely run at higher speeds. When the track is damaged, it results in speed restrictions, delays, and safety risks. A crack in the rail, a loose component, or a break in the ballast layer can affect train speed.

Recognizing the importance of rail tracks, Indian Railways has embarked on a comprehensive modernization program over the past few years. This work has included track renewal using modern machinery, advanced testing and inspection methods, mechanized maintenance, and safety fencing. These efforts have significantly transformed the rail network.

Since 2014, approximately 55,000 km of track has been renewed, improving safety and travel quality and reducing the need for frequent repairs. Approximately 44,000 km of track has been laid with 260-meter-long rail panels. Longer panels mean fewer joints, making train movement smoother and safer. More than 80,000 km of track now uses reinforced 60-kilogram rails, which ensure greater load capacity and faster speeds. While laying strong rail tracks is essential, detecting defects early is also crucial. Ultrasonic testing is used to detect hidden cracks. Approximately 3.62 million km of track and 22.5 million welds have been inspected. This has reduced rail and weld breakage by approximately 90 percent. This means that instead of repairing defects after they occur, they are detected and prevented. Other modern testing techniques are also being used on the railways, including magnetic testing for new welds, new machines for flash-butt welds, and a GPS-enabled system that measures train travel quality and pinpoints the exact location of a defective piece of track. The number of track machines on Indian Railways is projected to increase from 748 in 2014 to 1,785 by 2026. These machines perform track repairs, ballast cleaning, and other tasks more quickly, efficiently, and more uniformly than manual work. Machines have made a significant difference in cleaning the layer of ballast beneath the tracks. This ballast helps remove water, reduce vibrations, and maintain track strength. Over 100,000 km of rail infrastructure has been ground to remove defects on the track surface. This has made train journeys more comfortable and safe. With the number of trains increasing every year, the time available for maintenance is decreasing. Machines enable more work to be done in less time without disrupting train services. Safety is crucial not only on tracks but also where trains change lines. Therefore, Indian Railways has implemented several other improvements in addition to track replacement. Safety fencing has been installed along approximately 17,500 km, especially at locations where trains travel at speeds exceeding 110 km per hour. This reduces incidents of people and animals crossing the tracks. Where trains cross from one line to another, 36,000 new and stronger switches have been installed, and 7,500 special crossings have been installed. These last longer and allow trains to pass without jolts. Since 2019, wider and heavier sleepers have been installed, making the tracks more robust, especially in summer. Stronger sleepers have also been installed on bridges, and longer welded rails have been laid within yards. This has strengthened the entire railway network. The most obvious impact of track modernization is the increased train speed. The share of track capable of speeds of 130 km/h or more has increased from just 6 percent previously to nearly 23 percent. Similarly, track capable of speeds of 110 km/h or more has now reached 80 percent, up from only 40 percent previously. These improvements are showing their impact. In 2014-15, there were 135 major rail accidents, but by 2025-26, this number had dropped to just 16. Twelve years ago, 60 percent of India's rail tracks were limited to speeds below 110 km/h. Rail failures were common, and most maintenance was done manually. Now, about 80 percent of the rail network can handle speeds of 110 km/h or more. Rail and weld failures have been reduced by 90 percent, and approximately 1,800 track machines are operational. The Railways has also launched a new online system, called the Track Management System (TMS). It brings together all information related to track inspection, train travel quality, and track condition in one place. This allows the Railways to quickly identify where work is needed. is needed. These changes have had a major impact on the millions of passengers and businesses that rely on rail freight. Journey times have decreased and the railway network is more reliable than ever. Progress so far demonstrates how significant change is possible with continued hard work and investment.

मुरादाबाद में दर्दनाक हादसाः नो-एंट्री में घुसी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, पोते-पोती के सामने दादा की मौत

मुरादाबाद में 65 वर्षीय गीताराम की ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मौत हो गई, जबकि उनके पोते-पोती घायल हो गए। यह हादसा नो-एंट्री जोन में गलत दिशा से आ रही ट्रॉली के कारण हुआ, जिससे यातायात व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।बच्चों को हर दिन की तरह स्कूल से लेने निकले 65 वर्षीय गीताराम देवलाल के लिए बुधवार का दिन जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दोपहर में वह अपने पोते कियांश (7) और पोती आराध्या (10) को स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे।

बुद्धि विहार स्थित सेंट मेरी स्कूल के पास गोल चक्कर पर पहुंचते ही सामने से गलत दिशा में आ रही बजरफुट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गीताराम और कियांश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक पर पीछे बैठी आराध्या के हाथ और पैर में चोट आई। देर रात उपचार के दौरान गीताराम ने दम तोड़ दिया।दाऊ दयाल खन्ना नगर स्थित चाऊ की बस्ती तारों वाली ज्यारत निवासी गीताराम देवलाल बुधवार दोपहर रोज की तरह दोनों बच्चों को स्कूल से लेने घर से निकले थे।स्कूल से बच्चों को लेकर जैसे ही वह बुद्धि विहार आवास विकास स्थित सेंट मेरी स्कूल के पास गोल चक्कर पर पहुंचे, सामने से गलत दिशा में आ रही ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि गीताराम और कियांश गंभीर रूप से घायल हो गए। आराध्या भी सड़क पर गिरने से चोटिल हो गई, हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्काल तीनों घायलों को चिड़ियाटोला स्थित वर्धमान अस्पताल में भर्ती कराया।

लोगों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मझोला थाना इंस्पेक्टर विनीत खेवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को भी हिरासत में लिया।इधर, हादसे की जानकारी मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मझोला थाने में तहरीर दी। डॉक्टरों ने गीताराम की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें रेफर करने की सलाह दी।इसके बाद परिजन उन्हें कांठ रोड स्थित कासमॉस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कियांश और आराध्या को उपचार के बाद घर भेज दिया गया।हादसे ने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नो-एंट्री के बावजूद बजरफुट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंची और गलत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी।

लोगों के बीच वाहन के अवैध खनन से जुड़े होने और किसी रसूखदार के संरक्षण में होने की चर्चा भी है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इन पहलुओं के साथ ही पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।पुलिस ने गीताराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके परिवार में तीन बेटे आशीष, दीपक और सूरज हैं। छोटे बेटे सूरज ने कहा, पिताजी के जाने के बाद हमारे हरे-भरे पेड़ की जैसे जड़ें हिल गई हैं। बुधवार को बच्चों को स्कूल से लेने निकले गीताराम की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए खुशखबरी: IHGF दिल्ली फेयर का स्टॉल शुल्क 8,500 से घटकर हुआ 2,500

वैश्विक अनिश्चितता के बीच हस्तशिल्प निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। EPCH ने IHGF दिल्ली फेयर का भागीदारी शुल्क 8,500 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया है। इसके अलावा मुरादाबाद के निर्यातक अवधेश अग्रवाल को तीसरी बार प्रदर्शनी समिति का अध्यक्ष चुना गया है।मुरादाबाद के निर्यातक अवधेश अग्रवाल तीसरी बार बने प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितता और बढ़ती लागत के बीच हस्तशिल्प निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की प्रशासनिक समिति की दिल्ली में हुई बैठक में आईएचजीएफ दिल्ली फेयर के लगातार दो संस्करणों शरद और वसंत में भागीदारी शुल्क छह हजार रुपये प्रति वर्गमीटर कम करने का निर्णय लिया गया। इसे ऐसे समझें कि प्रदर्शनी में 8,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर और जीएसटी लिया जाता था। इस निर्णय के बाद अब निर्यातक को 2,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर और जीएसटी देना होगा। साथ ही बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही देश के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्रों में डिजाइन, कौशल और साझा सुविधा केंद्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया।मौजूदा समय में निर्यातक टैरिफ संबंधी अनिश्चितता, बढ़ती ढुलाई लागत और बदलती वैश्विक मांग से जूझ रहे हैं। ईपीसीएच में मुख्य संरक्षक राकेश कुमार ने बताया कि ऐसे में मेले की भागीदारी दर में छह हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की कमी से खासकर छोटे और मध्यम निर्यातकों को राहत मिलेगी। इससे वे कम लागत में अपने नए उत्पाद विदेशी खरीदारों के सामने प्रदर्शित कर सकेंगे। ईपीसीएच अध्यक्ष डा नीरज खन्ना ने निर्यातकों की मांग पर बोर्ड मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा। जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं, मुरादाबाद में आधुनिक डिजाइन केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई। इसे डब्ल्यूजीएसएन के वैश्विक रुझान संबंधी संसाधनों से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे निर्यातकों को बदलते रंग, डिजाइन, सामग्री और जीवनशैली से जुड़े अंतरराष्ट्रीय रुझानों की जानकारी मिल सके। मुरादाबाद में नकद बिक्री गतिविधियों के लिए विशेष बजट का प्रस्ताव भी रखा गया। जोधपुर में कौशल केंद्र, सहारनपुर में साझा सुविधा केंद्र- जोधपुर के बसनी केंद्र को फर्नीचर और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए कौशल, नवाचार और प्रशिक्षण का आदर्श केंद्र बनाने की योजना है। बोरणाडा स्थित केंद्र के विस्तार के लिए आसपास की भूमि की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। सहारनपुर के साझा सुविधा केंद्र को मजबूत करने, आगरा के केंद्र का विस्तार करने और फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार के सहयोग से नया क्लस्टर केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर और कोलकाता को भी बढ़ावा- फैशन आभूषण क्षेत्र के लिए दिल्ली-एनसीआर में साझा सुविधा केंद्र बनाने और कोलकाता में बैग एवं आभूषण क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। कोलकाता परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन संस्था के माध्यम से एक करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी का प्रस्ताव रखा गया है। परिषद अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना के नेतृत्व में हुई बैठक में सदस्य निर्यातकों के व्यापक हित को प्राथमिकता देने पर जोर रहा। बैठक के फैसलों से साफ है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में निर्यातकों को लागत में राहत देने के साथ डिजाइन, कौशल, साझा सुविधाओं और बाजार विस्तार पर एक साथ काम करने की रणनीति अपनाई जा रही है। अवधेश अग्रवाल तीसरी बार बने प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष- मुरादाबाद के निर्यातक और एमएचईए के महासचिव अवधेश अग्रवाल को प्रदर्शनी समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी तीसरी बार मिली है। मुरादाबाद के निर्यात उद्योग के लिए इसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा है। प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष के तौर पर वह आयोजन की तैयारियों, निर्यातकों की भागीदारी और प्रदर्शनी से जुड़े विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

BJP नेता पर केस दर्ज कराने वाली सचिव निलंबित, मुरादाबाद गोशाला में चारे के नाम पर मिला भारी घपला

मुरादाबाद की गोवर्धनपुर अस्थायी गोशाला में सरकारी दर से अधिक दाम पर भूसा-चारा खरीदने के मामले में सचिव स्वाति चौहान को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के निरीक्षण में यह अनियमितता सामने आई,

जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए।शाहजहांपुर के डीपीओ को भेजे गए निर्देश, प्रशासक पर भी हो सकती है कार्रवाईमूंढापांडे ब्लाक की गोवर्धनपुर अस्थायी गोशाला में भूसा और हरा चारा सरकारी निर्धारित दर से महंगी कीमत पर खरीदा गया। निरीक्षण में यह गड़बड़ी सामने आते ही अपर मुख्य सचिव एवं पशुपालन विभाग के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई। साथ ही सचिव स्वाति चौहान को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

सचिव की मूल तैनाती शाहजहांपुर में है और वह मुरादाबाद में अटैच चल रही हैं। निलंबन की कार्रवाई के लिए शाहजहांपुर के जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया। देर रात को निलंबन आदेश भी जिला विकास अधिकारी के पास आ गया।

बुधवार को अपर मुख्य सचिव ने मूंढापांडे ब्लाक की गोवर्धनपुर और अक्का पांडेय भोजपुर स्थित अस्थायी गोशालाओं का औचक निरीक्षण किया। गोवर्धनपुर में चारे की खरीद से संबंधित अभिलेख खंगाले गए तो सरकारी दर और खरीद में बड़ा अंतर मिला।बताया गया है कि अभिलेखों के मुताबिक भूसा करीब 450 रुपये और हरा चारा करीब 200 रुपये अधिक कीमत पर खरीदा गया था। अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गोवंशों के चारे की खरीद में भी यदि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है तो इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार से गोशाला की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।

सीवीओ डॉ. सुनील दत्त प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया से फोन पर बात कर गोवर्धनपुर की सचिव और निवर्तमान ग्राम प्रधान व प्रशासक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ चारा खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच कराकर सरकारी धन की रिकवरी कराने के निर्देश दिए हैं।

निवर्तमान ग्राम प्रधान अनिता देवी के पति एवं प्रधान प्रतिनिधि पंकज उर्फ विक्की के खिलाफ भी कार्रवाई को कहा। वहीं अक्का पांडेय भोजपुर की गोशाला में निरीक्षण के दौरान गोवंशों के कीचड़ के बीच रहने की स्थिति देखकर अपर मुख्य सचिव भड़क गए। उन्होंने सचिव और निवर्तमान ग्राम प्रधान को 10 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

हाल में ही भाजपा जिला पंचायत सदस्य समेत चार पर कराया था मुकदमा

निलंबित सचिव स्वाति चौहान ने हाल में ही भाजपा जिला पंचायत सदस्य समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले भी वह एक प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं।

संक्षिप्त समाचार

गिराया जाएगा दो करोड़ से ज्यादा में बना तीन मंजिला मकान!, नोटिस हुआ चस्पा; सपा के इस विधायक से है कनेक्शन

संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के तीन मंजिला मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया है। इसके साथ ही इसे गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सपा विधायक इकबाल महमूद की वक्फ संपत्ति पर मोहल्ला डेरा सराय में बने किरायेदार आरिफ के तीन मंजिला मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया है। निर्माण 15 दिन में गिराने का समय दिया है। इसके लिए बुधवार को मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। यदि इस अवधि में यह मकान नहीं गिराया जाता है तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूला जाएगा। यह आदेश जिलाधिकारी की अदालत से अपील खारिज होने के बाद जारी किया गया। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि तीन मंजिला निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया था। यह मकान मोहल्ला डेरा सराय में मौलाना आरिफ पुत्र अय्यूब अहमद उर्फ छिद्दा पहलवान के नाम से दर्ज है। किरायेदार अय्यूब अहमद पुत्र मकबूल अहमद का नाम भी इसमें शामिल है। मुतवल्ली के तौर पर नवाब इकबाल महमूद का नाम भी जुड़ा है। सुनवाई के बाद 5 फरवरी को इस निर्माण को अवैध घोषित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत गिराने का आदेश दिया गया है।डीएम कोर्ट ने अपील खारिज की-मकान अवैध घोषित किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ 17 मार्च को डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। डीएम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने के पुराने आदेश को बरकरार रखा है।दो करोड़ रुपये से ज्यादा मकान में खर्च होने की चर्चा- मोहल्ला डेरा सराय में बने इस मकान पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने की चर्चा है। तीन मंजिला मकान का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। करीब 400 गज में बने इस मकान का अभी निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। किरायेदार आरिफ विधायक के करीबी हैं। वर्षों पहले यह जमीन मुतवल्ली ने दी थी।वक्फ-अल-औलाद है जमीन-डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि वक्फ-अल-औलाद का अर्थ है कि जमीन/संपत्ति को वक्फ करके उसकी आय या लाभ वक्फकर्ता की संतान/परिवार के हित के लिए होता है। यह साधारण निजी जमीन की तरह बेचने या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी वक्फकर्त्ता की संतान मुतवल्ली बनकर निभाती है।विधायक बोले- हमें नहीं पता किस जमीन पर बना था मकान-सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हमारे दादा नवाब आशक हुसैन खां ने बहुत सी जमीनों को वक्फ-अल-औलाद कर दिया था। इसके वर्तमान में हम मुतवल्ली हैं। हमारी जमीनों पर तमाम लोगों ने मकान बना रखे हैं। हम किराया तक नहीं लेते हैं। जो तीन मंजिला मकान बना है उसकी जमीन हमारी है लेकिन निर्माण जिसने किया है यह उसकी जिम्मेदारी है। अभी हमें यह भी नहीं पता है कि यह जमीन कहां है। यह जानकारी कराई जाएगी।

बजरंग दल नेता की मौत पर मिलक में उबाल! सड़क से गांव तक प्रदर्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच लखीमपुर पहुंचा शव

रामपुर के मिलक में बजरंग दल नेता सूरज पटेल की मौत के बाद आक्रोश जारी है। आरोपी आदेश शंखधार की गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली और बस अड्डे पर विरोध किया। गांव पहुंचे शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कोतवाल व वरिष्ठ उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर करने की मांग पर अड़े हैं। रामपुर के मिलक में बजरंग दल नेता सूरज पटेल की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को भी आक्रोश बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने सुबह कोतवाली और बिलासपुर बस अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के आरोपी को गिरफ्तार करने के दावे के बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी सुबह 8 बजे कोतवाली के सामने जमा हुए, जहां पुलिस ने उन्हें हटाया। इसके बाद भीड़ बिलासपुर बस अड्डे पर इकट्ठा हुई और सुबह 10 बजे तक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। घर बुलडोजर चलाना और कोतवाल मनीराम का तबादला शामिल हैं।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

228 कंपनियों ने 9,426 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे, हजारों लोगों को मिला रोजगार

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 5.0 में बरेली के लिए किए गए निवेश के करार अब कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। जिले में 337 एमओयू के जरिए 19,637 करोड़ रुपये के निवेश का करार हुआ था। उद्योग विभाग के मुताबिक इनमें से 228 कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लेकर धरातल पर आ चुकी हैं। करीब 9,426 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से अब तक 13,384 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है।जीबीसी-5.0 के दौरान बरेली के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभाग के पोर्टल पर अब तक करीब 4,890 करोड़ रुपये की निवेश प्रगति दर्ज हो चुकी है। विभाग के अनुसार कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में निवेश और रोजगार दोनों के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है।

किस कंपनी ने कितना किया निवेश- बरेली में बड़े निवेशकों में ओमेक्स सिटी का प्रोजेक्ट प्रमुख है। कंपनी ने करीब एक हजार करोड़ रुपये का काम धरातल पर पूरा किया है। इससे करीब 500 लोगों को रोजगार मिला है। रियल एस्टेट और हाउसिंग क्षेत्र में सक्रिय वाईसीएल बिल्डर ने करीब 250 करोड़ रुपये का निवेश किया। इससे करीब 60 लोगों को रोजगार मिला है। रिटेल क्षेत्र में डी-मार्ट ने करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश किया। इससे 100 लोगों को रोजगार मिला। वहीं एलए सिटी सेंटर मॉल ने करीब 73 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के साथ 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। शिक्षा के क्षेत्र में एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल ने करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 50 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा गैस उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली कार्बन सर्कल ने भी करीब 50 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजना पर काम शुरू किया है।

15 हजार करोड़ के लक्ष्य से आगे का बड़ा प्रस्ताव- जीबीसी-5.0 में जिले के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जबकि कुल प्रस्तावित एमओयू का आंकड़ा 19,637 करोड़ रुपये पहुंचा। यानी निवेशकों ने लक्ष्य से अधिक निवेश की रुचि दिखाई। हालांकि अब विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन प्रस्तावों को वास्तविक निवेश में बदलने की है। उद्योग विभाग के अनुसार करीब 44.57 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जल्द पूरा किए जाने की स्थिति में हैं।

क्या बोले अधिकारी- बरेली के उद्योग उपायुक्त विकास यादव ने बताया कि जीबीसी-5.0 के तहत बरेली में हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए लगातार कंपनियों से संपर्क और समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जिन कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, उनके निवेश और रोजगार की प्रगति पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। शेष निवेश प्रस्तावों को भी जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य एमओयू को वास्तविक निवेश और रोजगार में बदलना है।

विप्रा शर्मा पर एक और रिपोर्ट दर्ज, विश्वविद्यालय का लिपिक, ठगी में दिया साथ

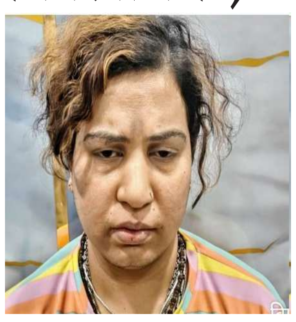

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय का क्लर्क फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा का खास गुर्गा निकला। वह छात्रों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर विप्रा के जरिये ठगी करता था। उसके खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शाहजहांपुर निवासी पुष्पेंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में जिक्र किया है कि उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध पुवायां स्थित महाविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स किया था। इसी दौरान रुहेलखंड विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर तैनात देवप्रकाश से जान पहचान हो गई। देवप्रकाश ने बताया कि उसका संपर्क आईएएस अधिकारी डॉ. विप्रा शर्मा से है। वह रुपये लेकर सरकारी नौकरी लगवा देंगी। अगर नौकरी नहीं लगी तो रुपये वापस करा दिए जाएंगे। देवप्रकाश के साथ पुष्पेंद्र ग्रीन पार्क स्थित विप्रा के घर गए। इसके बाद इन लोगों ने राजस्व विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सात लाख रुपये झटक लिए। बाद में पता चला कि क्लर्क देवप्रकाश और विप्रा अपने गिरोह के साथ मिलकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते हैं। देवप्रकाश ने कई और लोगों को यह बताकर शिकार बनाया था कि विप्रा ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। देवप्रकाश पर पहले भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब दोबारा उसके खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बताते हैं कि देवप्रकाश का नाम लगातार सामने आने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। उसे विवि के कृषि -संकाय में जरूर भेज दिया गया है।

वारावफात को लेकर प्रशासन अलर्ट :गड्ढे व लटकते तार होंगे दुरुस्त, 12 फीट से अधिक ऊंचा नहीं होगा डीजे

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। ईद-ए-मिलाद उल नबी (बारावफात) को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने गुरुवार को आईएमए हाल में पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में 24 व 25 अगस्त को निकलने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी के मार्गों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और आयोजकों से जानकारी ली गई। जुलूस मार्गों पर गड्ढे, लटकते विद्युत तार, साफ-सफाई और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सामने आने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जुलूस से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरेली की गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को हर हाल में कायम रखा जाए। निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने और कोई नई परंपरा शुरू नहीं करने की अपील की। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि सभी अंजुमनों से पांच जिम्मेदार लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी समस्या पर तत्काल समन्वय किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि डीजे जमीन से 12 फीट से अधिक ऊंचा न हो, गैर-परंपरागत रूट न अपनाया जाए तथा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर ने छात्राओं को दिए सफलता के मंत्र

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत वीरांगना रानी अवन्तीबाई लोधी महिला महाविद्यालय में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र में गुरुवार को 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की,ढ्ढक्र-1 इशिता किशोर, संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं वर्तमान उपजिलाधिकारी सदर बरेली ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने यूपीएससी/यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम की समझ, समय प्रबंधन, नोट्स बनाने, नियमित अध्ययन और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया। छात्राओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। समय प्रबंधन पर उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे प्रभावी अध्ययन तथा नियमित रिवीजन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि किसी विषय को उसी दिन, 3, 7, 15 और 30 दिन बाद दोहराने से याददाश्त मजबूत होती है। अंत में उन्होंने छात्राओं को दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

यातायात जागरूकता आर्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, कर्मचारी नगर, बरेली में एंटी क्राइम एंटी करप्शन मिशन भारत ट्रस्ट एवं यातायात पुलिस बरेली के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एंटी क्राइम एंटी करप्शन मिशन भारत ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष कमल जीत सिंह, यातायात पुलिस बरेली के टीआई विपिन कुमार राघव एवं टीएसआई गजेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा सरस्वती वंदना के साथ किया।

प्रतियोगिता में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरा। बच्चों ने यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था से संबंधित आकर्षक चित्र बनाकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनुज वर्मा, द्वितीय स्थान पवन तथा तृतीय स्थान इकरा अंसारी ने प्राप्त किया। विजेता छात्र-छात्राओं को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान टीआई विपिन कुमार राघव, टीएसआई गजेन्द्र शर्मा एवं कमलजीत सिंह ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा सड़क पार करते समय सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक शशांक सक्सेना द्वारा यातायात जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए टीआई विपिन कुमार राघव, टीएसआई गजेन्द्र शर्मा, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल संदीप प्रजापति एवं एंटी क्राइम एंटी करप्शन मिशन भारत ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष कमलजीत सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन कविशा जी ने किया। स्कूल के प्रबंधक शशांक सक्सेना एवं प्रधानाचार्य ज्योति अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, आयोजकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में सविता शर्मा, संजय शर्मा, नीरू अरोड़ा, भगवान दास, रवि राठौर, शहादत हुसैन, शहजिल अंसारी, हस्सान रजा सहित स्कूल का समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के माध्यम से समाज में 卐सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा卐 का संदेश पहुंचाना और विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बनाना रहा।

शिवपुरी में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर रोक

◆ आदेश का उल्लंघन करने वालों पर ढ्ढञ्ज अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी कार्रवाई

क्यूँ न लिखूँ सच / राजकुमार शर्मा (कटारे) शिवपुरी, जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने तथा आमजन के जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक, भड़काऊ या उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो एवं ऑडियो प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है, जिनसे धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़क सकती हैं अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होने की संभावना हो। ऐसी पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर के आदेश में फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों के प्रसारण को भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है कि उनके ग्रुप में इस प्रकार की भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित न हो।

आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति या समुदाय के बीच घृणा, वैमनस्यता पैदा करने, हिंसा के लिए उकसाने अथवा लोगों को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति, संगठन या समुदाय को एक स्थान पर एकत्र होकर कानून व्यवस्था या लोकशांति भंग करने के लिए उकसाने वाले संदेशों पर भी रोक रहेगी।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईटी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी संदेश, फोटो या वीडियो को शेयर अथवा फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें और अफवाहों से बचें।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए - 9027776991

संक्षिप्त समाचार

दस लाख और स्कॉर्पियो न दी तो थाने के बाहर दिया तीन तलाक

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। एक महिला ने अपने पति सहित ससुराल के सात सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उससे दस लाख रुपये रुपये और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर उसे थाने के बाहर तीन तलाक दे दिया गया। किला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी पीड़िता ने गुरुवार को उपजा प्रेस क्लब में हुई एक प्रेसवार्ता में दी। महिला ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था। इस संबंध में उसने प्रेमनगर थाने में एक दिसंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने 18 मई 2026 को निकाह कर लिया। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे। महिला ने आरोप लगाया कि कई बार उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उसने सात जून 2026 को किला थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया था। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर किला थाना पुलिस ने 22 जून 2026 को दोनों पक्षों को थाने बुलाया था। महिला भी वहां पहुंची थी। थाने के बाहर शौहर व उसके परिवार के छह लोगों ने उसे गालियां दीं। उन्होंने दहेज की मांग की। शौहर ने उसे थाने के गेट पर ही तीन तलाक दे दिया। जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

छात्रा को मारकर खेत में दफनाया, पुलिस ने कब्र से शव निकालकर कराया पोस्टमार्टम

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। कथित रूप से ऑनर किलिंग की एक घटना ने सनसनी मचा दी है। पुलिस ने कब्र से छात्रा का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि पीएम में ये साफ नहीं हुआ है कि छात्रा की हत्या कैसे की गई? इसलिए बिसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए छात्रा के कुछ परिजनों को हिरासत में लिया है। घटनाक्रम अलीगंज थाना क्षेत्र के हाफिजगंज का है। एक छात्रा की मौत के बाद उसका शव खेत में दफना दिया गया था। घटनाक्रम कई दिन पुराना है। मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो अब पुलिस ने बुधवार को छात्रा का शव कब्र से निकालकर पैनल के जरिये पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों ने स्लाइड तैयार की है। बिसरा सुरक्षित किया है। अब इसकी जांच से मौत का कारण साफ होगा।

लंबित मानचित्रों पर बीडीए का वार, हर गुरुवार समाधान दिवस से निस्तारण की रफ्तार होगी तेज

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने आमजन की सुविधा और भवन मानचित्रों के त्वरित निस्तारण के लिए बड़ी पहल की है। माह सितंबर से प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्राधिकरण सभागार में 'मानचित्र समाधान दिवस' आयोजित किया जाएगा। इस पहल में आवेदक और आर्किटेक्ट सीधे संबंधित अधिकारियों से संवाद कर मानचित्र स्वीकृति से जुड़ी तकनीकी आपत्तियों एवं लंबित मामलों का समाधान करा सकेंगे। आवश्यक अभिलेख पूर्ण होने पर लो-रिस्क भवन मानचित्रों के उसी दिन निस्तारण/अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाई-रिस्क मानचित्रों में भू-उपयोग संबंधी मामलों में तेजी लाने के साथ ही शमन मानचित्रों की समस्याओं का भी नियमानुसार समाधान किया जाएगा। बीडीए का उद्देश्य है कि लोगों को मानचित्र संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनभागीदारी, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के जरिए 'जनहित सर्वोपरि' के संकल्प को साकार करते हुए मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाएगा।

चाकू से गला रेतकर विवाहिता की हत्या

अमेठी में घर में मौजूद 26 वर्षीय विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मायके वालों ने ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल से धारदार हथियार मिले हैं और मृतका का मोबाइल भी गायब बताया गया है।अमेठी के पूरे चितई के पूरे दीवान गांव में बृहस्पतिवार को घर में मौजूद विवाहिता पूनम (26) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसके गले और चेहरे पर धारदार हथियार के निशान मिले। मायके वालों ने ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर ससुरालीजनों के खिलाफ प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज की है।

सतनवाड़ा थाने में अचानक पहुंचीं SP यांगचेन डोलकर भूटिया, रिकॉर्ड से लेकर हवालात तक किया निरीक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच / राजकुमार शर्मा (कटारे) शिवपुरी। अपराधों पर लगाम कसने और थाना स्तर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने गुरुवार को थाना सतनवाड़ा का निरीक्षण किया। स्क के अचानक थाने पहुंचने से पुलिसकर्मियों में भी हलचल रही। उन्होंने थाने में संधारित रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण रजिस्टर, मालखाना और हवालात का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्क ने थाना परिसर की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से थाने पर की जा रही कार्यवाहियों और लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अपराध नियंत्रण तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। रात की गश्त में बढ़ाएं सतर्कता- स्क ने रात्रि गश्त में अधिक से अधिक पुलिस बल लगाने और क्षेत्र में सतर्कता के साथ गश्त करने के निर्देश दिए। साथ ही थाने की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा ष्टष्टञ्जङ्क कैमरों को हर समय चालू रखने पर जोर दिया। वारंट और लंबित मामलों पर सख्ती- निरीक्षण के दौरान लंबित वारंटों की तामीली, लंबित अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी और मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया। स्क ने ष्टरू हेल्पलाइन और अन्य लंबित शिकायतों का समय पर निराकरण करने तथा फरियादियों की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला अपराध और संपत्ति संबंधी मामलों पर विशेष जोर- महिला संबंधी अपराधों में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना देने और पीड़िता को आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ चोरी या अन्य संपत्ति की बरामदगी सुनिश्चित करने को कहा गया। स्क ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि थाना क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जाए और अपराध व अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रखी जाए।

गोवर्धन पूजा में झूमे श्रद्धालु, भक्ति में डूबा कथा पंडाल

क्यूँ न लिखूँ सच /बिलारी । श्रीराम मैरिज होम में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा व्यास परम श्रद्धेय श्री राधा माधव दास जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन ने भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं के साथ गोवर्धन पूजा एवं गिरिराज महाराज की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा प्रसंग सुनकर श्रद्धालु महिलाएं झूम-झूमकर नृत्य करने लगीं और पूरा कथा पंडाल भक्तिरस में डूब गया। कथा व्यास ने बताया कि जब ब्रजवासियों पर इंद्रदेव के प्रकोप के कारण मूसलाधार वर्षा का संकट आया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर समस्त ब्रजवासियों एवं गौवंश की रक्षा की। गोवर्धन प्रसंग भगवान की अपने भक्तों के प्रति करुणा, संरक्षण और अटूट प्रेम का प्रतीक है। कथा के दौरान गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने गिरिराज महाराज के समक्ष श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित कर सुख-समृद्धि, परिवार के मंगल और सर्वजन कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान कथा पंडाल में गिरिराज महाराज की जय और राधे-राधे के जयघोष गूंजते रहे। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को अहंकार का त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। गोवर्धन लीला प्रकृति, गौसेवा और समस्त जीवों के प्रति करुणा एवं कृतज्ञता का भाव रखने की प्रेरणा देती है। कथा श्रवण के दौरान पंकज चौहान, अशोक माथुर, दक्ष चौधरी, राजेश ठाकुर, श्रीकुमार गुप्ता, बंटी गुप्ता, जगपाल सिंह, पिंटू चौधरी, संजीव शर्मा, सुधीर ठाकुर, राजीव भारद्वाज, शीलू गुप्ता, कुलदीप चौधरी, गोरेलाल, ओम शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाकालेश्वर सेवा समिति के महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 23 अगस्त को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा को संगीतमय बनाने में सोनू यादव, मोहन, मनीष, वीरेश चौधरी, विक्रम चौधरी और निशू यादव का सहयोग रहा।

बरेली में दर्दनाक हादसा: वाहन की टक्कर से युवक और उसकी मौसी की मौत, हाईवे पर क्षत-विक्षत मिले शव

बरेली में बृहस्पतिवार दोपहर बड़ा बाइपास पर दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार युवक देव पटेल (23) और उनकी मौसी नीलम पटेल (24) की मृत्यु हो गई। देव की बाइक को कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया था। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बड़ा बाइपास पर बृहस्पतिवार दोपहर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी मौसी की मौत हो गई। कोई अज्ञात वाहन उनकी बाइक को टक्कर मारकर चला गया। लालपुर चौराहे के पास हुई इस घटना में दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। हाईवे पर सूचना पर पहुंची इज्जतनगर थाना पुलिस ने शवों की पहचान कर परिवार को सूचना दी। इज्जतनगर थाना प्रभारी को करीब ढाई बजे इस हादसे की सूचना मिली। वह मौके पर पहुंचे तो दोनों के शव व बाइक सड़क पर पड़े मिले। पुलिस ने मृतकों की पहचान देव पटेल (23) और नीलम पटेल (24) के रूप में की। पता लगा कि देव पटेल नत्थू रम्पुरा गांव के प्रधान का बेटा था और नीलम उसकी मौसी थीं। नीलम सुरेंद्र पटेल की पत्नी थीं, जो कैंट क्षेत्र के गांव बरी नगला के निवासी हैं। मौसी को दवा दिलाने गया था भांजा - नीलम अपने परिवार के साथ कई साल से बारादरी थाने के गांव डोहरा में मकान बनाकर रह रही थीं। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था।

आजम पर कस रहा शिकंजा: सपा नेता की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें, छापे से पहले ईडी ने 84 मुकदमों का खंगाला रिकॉर्ड

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले सपा नेता आजम खां की कुंडली खंगाल ली है। बीस दिन पहले रामपुर पुलिस से सपा नेता व उनके परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों का चिट्ठा मांगा गया था। पुलिस ने आजम खां पर दर्ज 84 मुकदमों का पूरा रिकॉर्ड ईडी को भेजा था, जिसके बाद अब ईडी पूरी तैयारी के साथ जांच-पड़ताल कर रही है।रामपुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामलों की भी चर्चा तेज हो गई है।जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के साथ ही जल निगम भर्ती घोटाला और नियम विरुद्ध सीवरेज सिस्टम तैयार कर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी लंबित है। ऐसे में आने वाले दिनों में आजम खां की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में बुधवार को ईडी ने विश्वविद्यालय परिसर समेत आजम खां के करीबियों और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी की टीम ने वित्तीय लेनदेन, ट्रस्ट की आय-व्यय और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल धन के स्रोत से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले। जांच का दायरा बढ़ने से अब विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई बड़ी रकम के स्रोत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।इसके अलावा जल निगम में भर्ती घोटाले का मामला भी आजम खां के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। उनके मंत्री रहते जल निगम में हुई भर्तियों को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच के दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई थी। वहीं रामपुर में सीवरेज सिस्टम के निर्माण में नियमों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा मामला भी लंबित है।

जानकारों के मुताबिक अलग-अलग मामलों में चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई के बाद पुराने मामलों की फाइलें भी चर्चा में आ गई हैं। यदि जांच में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े नए तथ्य सामने आते हैं तो आजम खां की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में पहले भी हो चुकी है जांच- जौहर यूनिवर्सिटी और सपा नेता आजम खां से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। वर्ष 2023 में आयकर विभाग की टीम ने आजम खां के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था।

आयकर विभाग की यह कार्रवाई लगातार तीन दिन तक चली थी। इस दौरान टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की थी।

आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान आजम खां के आवास के अलावा उनसे जुड़े लोगों और संस्थानों से संबंधित कई ठिकानों पर भी टीम पहुंची थी। तीन दिनों तक चली जांच के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य कागजात खंगाले थे। कार्रवाई को लेकर उस समय रामपुर में काफी हलचल रही थी। इससे पहले 2022 में भी ईडी ने छापे की कार्रवाई की थी।

अब 494 करोड़ रुपये के खर्च के स्रोत की जांच- अब 2026 में जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद पुराने मामलों की भी चर्चा शुरू हो गई है। ईडी की मौजूदा जांच में ट्रस्ट की आय, खर्च, दान और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल धन के स्रोत को खंगाला जा रहा है। खासतौर पर 494 करोड़ रुपये के खर्च के स्रोत और ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियां जांच के केंद्र में हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा का रहा कड़ा पहरा- मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जौहर यूनिवर्सिटी में बुधवार को ईडी की कार्रवाई के चलते दिनभर बारिश के बाद भी गहमागहमी का माहौल रहा। सुबह से ही यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। परिसर के भीतर सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही कि बिना अनुमति किसी को भी परिसर में आने-जाने की इजाजत नहीं दी गई।

ईडी की टीमों ने यूनिवर्सिटी परिसर में अलग-अलग स्थानों पर जांच की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मी लगातार निगरानी करते रहे। परिसर के भीतर एक टीम गश्त करती भी दिखाई दी। ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी के आसपास भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। दिनभर पुलिस बल की मौजूदगी के चलते मुख्य गेट पर लोगों की नजरें टिकी रहीं।

ईडी की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। सुरक्षा के मद्देनजर यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बनी रही। कार्रवाई को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन या ईडी की ओर से फिलहाल विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यूनिवर्सिटी पर सीओ टांडा पंकज पंत जवानों के साथ मुस्तैद रहे।

हर ठिकाने पर तैनात रही फोर्स- रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा पीपल टोला स्थित सीके एसोसिएट के दफ्तर व आवास पर भी ईडी ने कार्रवाई की। इस दौरान यहां पर भी सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम लगी रही। इसी तरह शौकत अली रोड पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई।

छापे से पहले ईडी ने आजम खां पर दर्ज 84 मुकदमों का रिकॉर्ड खंगाला

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले सपा नेता आजम खां की कुंडली खंगाल ली है। बीस दिन पहले रामपुर पुलिस से सपा नेता व उनके परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों का चिट्ठा मांगा गया था। पुलिस ने आजम खां पर दर्ज 84 मुकदमों का पूरा रिकॉर्ड ईडी को भेजा था, जिसके बाद अब ईडी पूरी तैयारी के साथ जांच-पड़ताल कर रही है।

सूत्र बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के दौरान सरकारी जमीन, शत्रु संपत्ति पर कब्जों जैसे आरोपों पर आधारित एक शिकायत केंद्र सरकार से की गई थी। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए कुल खर्च का सवाल भी उठा था।

निर्माण में बाहरी लोगों के आर्थिक सहयोग के नाम पर काला धन खपाने के आरोप भी चर्चा में आए थे। इसके बाद एक तरफ आयकर विभाग सक्रिय हुआ था, जबकि ईडी की ओर से वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा आजम खां के जल निगम का अध्यक्ष रहते समय निगम में भर्ती घोटाले का मुद्दा उठने पर वर्ष 2022 में लखनऊ में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

इन दोनों एफआईआर के आधार पर जांच कर रही ईडी ने रामपुर पुलिस से उन पर पहले से दर्ज मुकदमों, चार्जशीट व ताजा स्थिति की डिटेल मांगी थी। पुलिस की ओर से आजम खां पर दर्ज 84 मुकदमों की एफआईआर, चार्जशीट की कॉपियां ईडी को भेजी गई थीं। पूरी रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अब ईडी ने अपने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ईडी अब पूरे सुबूतों के साथ मामले की जांच में जुटी है।

संक्षिप्त समाचार

रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा के लिए 1 सितंबर तक करें आवेदन, शिवपुरी से 196 बुजुर्ग जाएंगे

क्यूँ न लिखूँ सच / राजकुमार शर्मा (कटारे) शिवपुरी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शिवपुरी जिले के बुजुर्गों को रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। योजना के तहत विशेष ट्रेन 7 सितंबर 2026 को रामेश्वरम् के लिए रवाना होगी और 12 सितंबर को वापस लौटेगी।

इस यात्रा में शिवपुरी जिले के 196 बुजुर्ग तीर्थयात्री शामिल होंगे। इच्छुक पात्र बुजुर्ग 1 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसील, जनपद पंचायत, नगरपालिका एवं नगर परिषद कार्यालयों में पात्र आवेदकों के आवेदन प्राप्त किए जाएं। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को मिलेगा लाभ- योजना के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना तथा उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई है। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा करने में सक्षम होना जरूरी है। आवेदक किसी संक्रामक रोग से पीड़ित भी नहीं होना चाहिए। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्री यदि अपने साथ सहायक ले जाना चाहते हैं तो सहायक का आवेदन भी पृथक रूप से जमा करना होगा। सहायक की आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। अधिक आवेदन आए तो लॉटरी से होगा चयन- यदि पात्र आवेदकों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक होती है तो तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजना का लाभ एक व्यक्ति को एक बार ही मिल सकेगा। चयनित यात्रियों को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक और यात्रा पूरी होने के बाद रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचने का खर्च स्वयं वहन करना होगा। विशेष ट्रेन के निर्धारित समय से दो घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचने की जिम्मेदारी भी यात्री की होगी।आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी- आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। इसके साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, आयकरदाता नहीं होने का स्व-घोषणा पत्र, चिकित्सक का प्रमाण पत्र तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूर्व में यात्रा नहीं करने संबंधी स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। प्रशासन ने पात्र एवं इच्छुक बुजुर्गों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन जमा करने की अपील की है।

डंपर में बाइक पीछे से घुसने से , बाइक चालक घायल

क्यूँ न लिखूँ सच /शेर सिंह/ भुता। बरेली बीसलपुर मुख्य मार्ग पर पडो़ली गांव से पास बीसलपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार पीछे बैठे अपने बेटे को लेकर डंपर में में पीछे से जा घुसा। जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भिजवा दिया है। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई। फिलहाल पीछे बैठा उसका बेटा सुरक्षित है। चालक अपना डंपर लेकर मौके से फरार हो गया है। बीसलपुर की ओर से राम मोहन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डड़िया हेतराम थाना भुता अपनी बाइक से पीछे बैठे अपने बेटे मुनीश उम्र लगभग 10 वर्ष बरेली की ओर जा रहे थे। कि अचानक बाइक चालक का ध्यान भटकने पर पड़ोली गांव के पास डंपर में पीछे की ओर से जा घुसा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर उसका 10 वर्षीय बेटा मुनीश के कोई चोट नहीं आई। इधर ट्रक चालक अपना डंपर लेकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस डंपर व चालक की तलाश कर रही है।

विधायक के आरोप पर पुजारी की सफाई, बोले- मंदिर में हर वर्ग के लोग पूजा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता

लखनऊ के काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर में जातिगत भेदभाव के आरोपों पर पुजारी ने सफाई दी है। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मंदिर में सभी वर्गों के लोग पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुजारी का समर्थन किया। मामले के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।लखनऊ के काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर में विधायक जय देवी कौशल की ओर से लगाए गए जातिगत भेदभाव और अपमान के आरोपों पर मंदिर के पुजारी शैलेंद्र बाजपेई ने बृहस्पतिवार को सफाई दी। उन्होंने विधायक के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मंदिर में पूजा-अर्चना को लेकर किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। मंदिर में सभी वर्ग और समाज के लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करने आते हैं।

पीपलखेड़ा में विद्युत मंडल का बड़ा कारनामा शमशाबाद वितरण केंद्र सर्विस स्टेशन सतपाड़ा

क्यूँ न लिखूँ सच / हाकम सिंह रघुवंशी/विदिशा/ ग्राम सुल्तानिया से सलैया रोड पर रोड पर सीसी पर खामे गड़े है जिससे आए दिन खतरा होने का अंदेशा बना रहता है क्योंकि रोड पर ही खंबे खड़े हैं सीसी हो गया है खम्मा बीच में रह गया है

ठेकेदार ने रोड डाल दिया बिजली विभाग ने अपना काम कर दिया चुकी लाइन शिफ्ट होना थी तो बगल में नई पोल खड़े हैं पर इन पर बिजली विभाग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है सुल्तानिया से सलैया रोड को डाले हुए लगभग 2 साल हो गए हैं लेकिन विभागीय अधिकारी संदीप नामदेव इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी तक लाइन शिफ्टिंग नहीं हुई है ठेकेदार और विद्युत मंडल इस दिशा में ध्यान ही नहीं दे रहा है में अंदेशा लग रहा है ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि कई बार मौखिक शिकायत करने के बाद भी लाइन की शिफ्टिंग नई हुई है

रोड क्रॉसिंग मे बड़े बहान निकलते हे वहां लाइन में आते रहते हैं जिससे कि आम लोगों को परेशानी होती है अब बड़ा सवाल यह है की सिंगल रोड से सुल्तानिया सलैया तक डबल लाइन हो चुकी है लाइन पूरी शिफ्ट होना था काम क्यों नहीं हुआ है ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया है विद्युत मंडल ने इस काम क्यों नहीं करवाया है या कहीं मिली भगत से इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग किया कि इस विषय पर जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और लाइन को शिफ्ट किया जाए ।

डीएम ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए शत-प्रतिशत प्रगति के निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच / बदायूँ जिलाधिकारी अवनीश राय ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ सी0एम0 डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सी0एम0 डैशबोर्ड पर प्रदर्शित अपने-अपने विभाग से संबंधित बिंदुओं एवं प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की नियमित समीक्षा कर उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने वादों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनीटरिंग की जाए। जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की समीक्षा कर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अंजुम बी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सीडीओ ने बैंकर्स के साथ बैठक कर लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

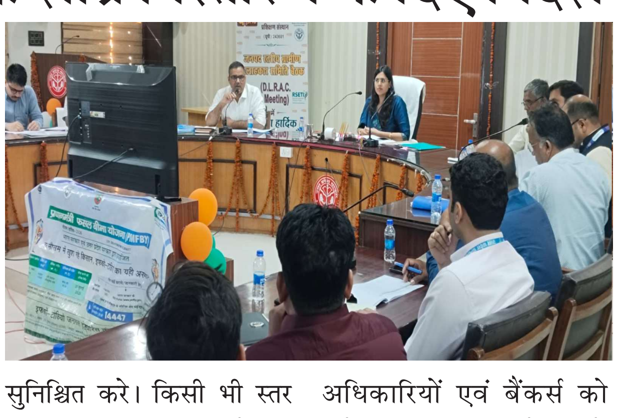

क्यूँ न लिखूँ सच / बदायूं- मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला ने विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समस्त बैंकर्स को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित लंबित ऋण प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं में लंबित आवेदन पत्रों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा अधिकारी एवं बैंकर्स एक-दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय आपसी समन्वय से प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने बैंक शाखाओं में लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए कई प्रकरण लंबित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक बैंक अपने यहां लंबित प्रकरणों का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए उनका समय से निस्तारण सुनिश्चित करे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बैंकर्स से अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला ऋण-जमा अनुपात की प्रथम तिमाही जून 2026 की प्रगति, वार्षिक ऋण योजना 2026-27 की प्रथम तिमाही जून 2026 तक की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैंक शाखाओं द्वारा जारी आरसी की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं बैंकर्स मेहनत एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनके निस्तारण की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, बैंकर्स एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

थाना दातागंज पुलिस नें 24 घण्टे के अंदर लूट की घटना का किया खुलासा दो अभियुक्तगण को भेजा जेल

क्यूँ न लिखूँ सच / जनपद बदायूं में थाना दातागंज वादी नेत्रपाल पुत्र किशनपाल निवासी कस्बा म्याऊं थाना अलापुर, बदायूँ की थाना दातागंज क्षेत्र के ग्राम डहरपुर टोल प्लाजा के पास 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी रोककर गाडी सीज करवाने की धमकी देकर 50000/- रूपये की माँग करते हुये वादी उपरोक्त से जबरदस्ती 19200/- रूपये नगद व 800/- रूपये आनलाइन यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कराने एवं एक मोबाइल फोन लूट लेने की घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दातागंज पर मु0अ0स0 289/2026 धारा 308(2)/309(6) बीएनएस बनाम 04 अज्ञात पंजीकृत किया गया घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. हरिओम मथुरिया पुत्र रामसरन निवासी मोहल्ला नाहर खाँ सराय लालपुल चौराहा थाना कोतवाली बदायूँ 2. यश जोशी पुत्र सुभाष चन्द्र जोशी निवासी मोहल्ला जोशी, चौधरी सराय थाना कोतवाली बदायूँ को आज थाना दातागंज पुलिस द्वारा लूटे गये एक अदद मोबाइल, 10200 रूपये नगद मय घटना मे प्रयुक्त वैगनार गाडी (DLxCBS6126) सहित बसेला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 309(6) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 310(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित

क्यूँ न लिखूँ सच / बदायूं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देशानुसार जनपद बदायूँ में 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में श्री राज वीर सिंह, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बदायूँ एवं श्रीमती सुमन तिवारी, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक आहूत की गई। बैठक में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों एवं उसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारित किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित ऐसे अधिक से अधिक वादों एवं प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जनसामान्य को व्यापक रूप से सूचित एवं जागरूक किया जाए,

ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों से कहा गया कि प्री-लिटिगेशन विवादों को अधिकाधिक संख्या में चिन्हित कर नियत करते हुए पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण कराने का यथासंभव प्रयास किया जाए। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षकारों से समन्वय स्थापित किया जाए तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से विवादों के सरल, त्वरित एवं आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित करने पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से जनपद बदायूँ में किया जाएगा। संबंधित विभागों एवं अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

मिलजुल कर त्योहार मनाएं, शासन और कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करें: एसडीएम

क्यूँ न लिखूँ सच / राजेंद्र विश्वकर्मा /ईद मिलादुन्नबी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर कोतवाली में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक कोंच। ईद मिलादुन्नबी को लेकर आगामी 26 अगस्त को निकलने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी तथा रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पर्व को लेकर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई जिसमें अधिकारियों ने मिलजुल कर त्योहार मनाने और शासन व कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। एसडीएम अभिनव कुमार की अध्यक्षता, सीओ परमेश्वर प्रसाद एवं कोतवाल निगवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने जुलूस आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों से जुलूस मार्ग से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के बाबत जरूरी जानकारी हासिल की।

एसडीएम ने कहा कि परस्पर सौहार्द के साथ जुलूस निकालें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को कोई परेशानी उत्पन्न हो। सीओ ने कहा कि डीजे की ध्वनि और डीजे की लंबाई चौड़ाई पर विशेष ध्यान रखें। लोहे के पोल पर झंडे आदि न लगाएं। कोतवाल ने कहा कि जुलूस में अराजकतत्वों पर विशेष निगाह रखी जाएगी जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल जुलूस में रहेगा। इस मौके पर ईओ मोनिका उमराव, जेई बिजली देवेंद्र उपाध्याय, जुलूस के सदर एवं सभासद शमसुद्दीन मंसूरी, सभासद आजाद उद्दीन, काजी बशीर उद्दीन, मोहम्मद अहमद, हाफिज साबिर अली, एनुल आरफीन, नन्नू कुरैशी, हामिद बरकाती, फहीमुद्दीन, अशफाक गौरी, विहिप जिला मंत्री साकेत शांडिल्य, नगर अध्यक्ष संतोष तिवारी आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

खटखरी चौकी की कमान अब उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा के हाथों, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस

क्यूँ न लिखूँ सच / प्रदीप कुमार तिवारी कार्यकारी संपादक/ मऊगंज। शाहपुर थाना क्षेत्र की महत्वपूर्ण खटखरी चौकी की जिम्मेदारी अब उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा संभालेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के तहत मऊगंज पुलिस लाइन में पदस्थ उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा को खटखरी चौकी प्रभारी

नियुक्त किया गया है। उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा का पुलिस विभाग में पूर्व अनुभव भी रहा है। वे इसके पहले जबलपुर में पदस्थ रह चुके हैं। हाल ही में उनका स्थानांतरण जबलपुर से मऊगंज जिले में हुआ था, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन में पदस्थ किया गया था। अब उन्हें खटखरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास तौर पर हाल ही में खटखरी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद सामने आई कानून-व्यवस्था और यातायात की चुनौती को देखते हुए नए चौकी प्रभारी के सामने कई अहम जिम्मेदारियां रहेंगी। हादसे के बाद सड़क पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत करने, यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर नए चौकी प्रभारी का विशेष ध्यान रहेगा। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा के अनुभव और नेतृत्व में खटखरी चौकी की पुलिसिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। अब देखना होगा कि खटखरी चौकी की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को किस तरह बेहतर बनाते हैं।

22 अगस्त दिन शनिवार को निशुल्क नेत्र शिविर का आयो जन बड़ा मील कोंच में साथ ही आयुर्वेदिक केम्प आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच / राजेंद्र विश्वकर्मा /कोंच(जालौन)। दिनांक 22 अगस्त दिन शनिवार को एस एन गुप्ता पब्लिक स्कूल क्रय विक्रय समिति के सामने बड़ा मील कोंच में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है यह जानकारी इस निशुल्क नेत्र परीक्षण के आयोजक सुरेश गुप्ता बाबू जी

और राहुल गुप्ता अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से दी है उन्होंने बताया है कि इस शिविर में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट की डाक्टरों की टीम आ रही है यह नेत्र परीक्षण शिविर सुबह दस बजे से एक बजे तक चलेगा इस नेत्र परीक्षण शिविर ने जांच के उपरांत जिन मरीजों को मोतियाबिंद है उनको डाक्टरों की टीम अपने वाहन से आप्रेशन हेतु चित्रकूट निशुल्क ले जावेगी और आपरेशन के बाद उन्हें अपने ही वाहन से उन्हें उनके घर तक छोड़ने आएगी इस बार आयुर्वेदिक केम्प का आयोजन होगा जिसने डाक्टरों द्वारा निशुल्क परामर्श के साथ दवा आदि दी जावेगी उन्होंने लोगो से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की ।सभी कैंप में आने वाले लोग अपना आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर जरूर लाये।

यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से 10 हजार की घूस लेते पकड़ा गया वरिष्ठ सहायक

क्यूँ न लिखूँ सच / ब्यूरो / बरेली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने रंगे-हाथ घूसखोरी का मामला पकड़ा है। वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात मुहम्मद नावेद एक विद्यार्थी से 10 हजार रुपये की घूस ले रहे थे। जाल बिछाए खड़ी एंटी करप्शन टीम ने वरिष्ठ सहायक को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

एक विद्यार्थी की मार्कशीट पर उसकी मां का नाम गलती से सुनीता के बजाय उनीता दर्ज हो गया। वह नाम सही कराने के लिए यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। यहां वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात मुहम्मद नावेद ने विद्यार्थी से 10 हजार रुपये की मांग की। छात्र असहज हो गया। काफी मनुहार के बावजूद भी नावेद कम पर राजी नहीं हुआ। इस पर छात्र ने एंटी करप्श की टीम से संपर्क किया। टीम ने शिकायत की जांच के बाद वरिष्ठ सहायक को ट्रैप करने की योजना बनाई। गुरुवार को विद्यार्थी 10 हजार रुपये लेकर बोर्ड ऑफिस पहुंचा। यहां वरिष्ठ सहायक नावेद रूम नंबर 22 में बैठे थे। जैसे ही विद्यार्थी ने नावेद को रुपये दिए-घात लगाए बैठी टीम ने दबोच लिया।

एंटी करप्श की छापेमारी से बोर्ड ऑफिस में हलचल मच गई। टीम उसे पकड़कर बाहर लाई और गाड़ी में बिठाकर ले गई है।

Odisha's famous Chhena Poda was created by a mistake by a confectioner. The story behind Lord Jagannath's favorite offering is fascinating.

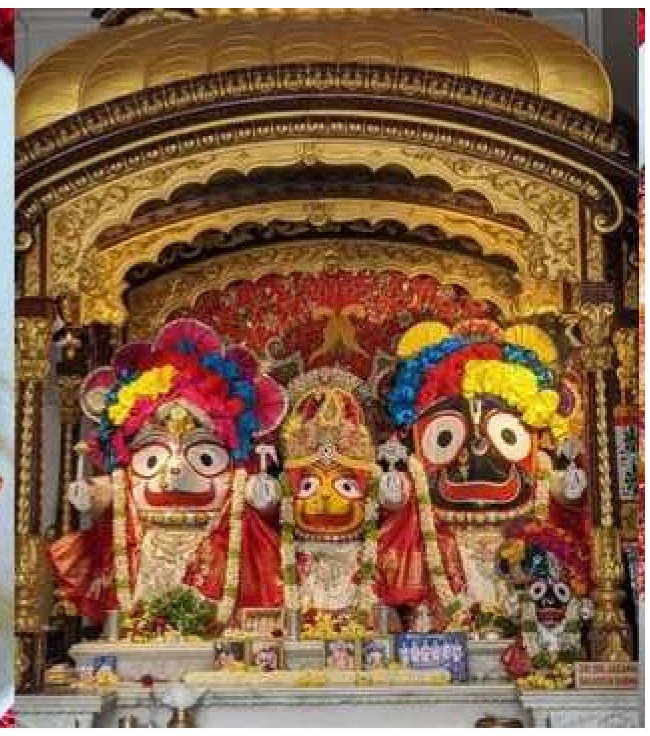

Chena Poda is a famous sweet of Odisha. This sweet was first created by a confectioner by chance. Chhena Poda, a sweet created by a mistake by a confectioner—made by Sudarshan Sahu of Nayagarh by mistake—is part of the 56 offerings at the Jagannath Temple. How can one mention Odisha without mentioning Chhena Poda? This sweet, offered to Lord Jagannath, is renowned for its distinctive aroma. But did you know that this dish, which has become an integral part of Odisha's food culture, was actually the result of a mistake? Yes, this is not a master chef's recipe, but a coincidental sweet that has now become an integral part of Odisha's culture. Let's find out how the amazing Chhena Poda was first made. The story of one night and the confectioner from Nayagarh - Chhena Poda originated in the 20th century in the town of Nayagarh, Odisha. The credit for creating this sweet goes to Sudarshan Sahu, the owner of a local sweet shop. It is said that one night, Sudarshan Sahu had a large amount of leftover chenna. Instead of throwing it away, he placed the mixture of sugar and some seasonings in a hot oven, which was still slightly warm after a long day's work. The mixture remained in the oven overnight. When he opened the oven the next morning, he was astonished to see a wonderful sweet. Thus was born Chhena Poda, now known as the taste of Odisha. How it got its name - Chhena Poda's meaning lies in its making process. In Odia, chenna means cottage cheese, and poda means burnt or roasted. It is not just a sweet, but an emotion for every Odia citizen. Today, it is in high demand at every sweet shop in Odisha, where it is prepared in various flavors of sugar or jaggery. Traditional Method and Unique Flavor - The recipe for Chhena Poda is quite interesting. It uses fresh chenna, sugar, and semolina. This mixture is wrapped in sal leaves. The sal leaves give it a distinctive smoky flavor and aroma. It is baked over low heat until its outer layer becomes golden brown and crispy. Religious Significance and Chhappan Bhog - Due to its unique and rich flavor, Chhena Poda quickly made its way from ordinary shops to temples. Today, it is part of the Chhappan Bhog offered to Lord Jagannath at the famous Jagannath Temple in Puri. This sweet is soon going to receive a GI tag, which will play a vital role in preserving its regional identity.

If your body is also giving these 7 signals, be careful! These could be signs of vitamin B12 deficiency.

Ignoring the symptoms of vitamin B12 deficiency can worsen the problem. Diet and supplements can help address the deficiency. Persistent fatigue and weakness are signs of vitamin B12 deficiency. Tingling in the hands and feet and memory problems. Neurological symptoms - correct vitamin B12 deficiency with diet or supplements. Our body gives us silent signals before any illness, all we need is to understand them. When there is a vitamin B12 deficiency, the body gives us such signals that it is very important to recognize them. However, many people take these signals lightly, which can prove fatal in the long run. Vitamin B12 deficiency in the body causes various physical and neurological symptoms, which are important to recognize in time. Let's learn about the symptoms of vitamin B12 deficiency. Signs of Vitamin B12 Deficiency: Fatigue and Weakness - If you constantly feel tired and weak, even after getting enough sleep, this could be a sign of a vitamin B12 deficiency. Digestive Problems - Problems like nausea, vomiting, or diarrhea can be caused by a vitamin B12 deficiency. Loss of Appetite and Weight Loss - Sudden loss of appetite and rapid weight loss without any effort are also signs. Mouth Sores and Swollen Tongue - B12 deficiency can cause the tongue to become swollen, red, and painful. Frequent mouth sores are also a common symptom. Yellowing of the Skin - Vitamin B12 deficiency can cause a slight yellowing of the skin, similar to jaundice, because it reduces the production of red blood cells. Irritability - Unexplained changes in temperament or feeling irritable over trivial matters can be signs of a vitamin B12 deficiency. Changes in behavior - A sudden change in a person's thinking pattern or normal behavior also indicates a vitamin B12 deficiency. Neurological symptoms of vitamin B12 deficiency - Tingling in hands and feet - If you repeatedly experience numbness or a tingling sensation in your hands or feet, don't take it lightly. Memory problems - Forgetting things or having trouble concentrating on a task indicates a serious B12 deficiency. Balance and walking problems - This deficiency damages the nervous system, which can lead to difficulty walking or speaking normally. How to prevent it? - Our bodies cannot produce vitamin B12 on their own. Therefore, this deficiency can only be addressed through diet and supplements. Its main sources are animal-based products, such as milk, eggs, and chicken. If you are a vegetarian, you can also take vitamin B12 supplements after consulting a doctor.

"Hey man! It's in my head, but it's not coming to my tongue..." If this happens to you, understand the science behind it.

Sometimes it feels like a word is stuck on my tongue, but I can't remember it. This is called the tip-of-the-tongue phenomenon. Feeling like a word is stuck on my tongue but I can't remember it is a common occurrence when my brain can't recall information.

This happens when my brain can't recall it. This is called the tip-of-the-tongue phenomenon. Have you ever tried to remember an old friend's name, a movie title, or a specific word, and it feels like it's right there on the tip of your tongue, but it just won't come out? You can tell the length of the word, its first letter, and even similar words come to mind, but the exact word is missing. If so, don't worry, you're not alone. In psychological terms, this experience is called the "tip-of-the-tongue" or TOT phenomenon. It's a mental state in which a person knows they know the information, but their brain can't recall it at a given moment. Why and how does this happen? Psychologists believe that our brain stores words or information in several different layers. When we memorize a word, the brain connects its meaning and its sound. TOT occurs when the brain reaches the meaning of the word but fails to connect it with its pronunciation. It can be considered a kind of short circuit, where you know who you're looking for, but their name gets stuck in the doorway of your mind. What do we feel during TOT? The most interesting thing about this phenomenon is that we remember many other things about the missing word, such as: - Word structure - People can often tell whether a word is short or long. - Sound - You may remember what a word sounds like or how many letters it has. - First letter - Sometimes a person remembers the first letter of the correct word. - Other words - The brain often recalls synonyms instead of the word itself. Reasons behind this: - Infrequent usage - This often happens with words that we rarely use in our daily lives. - Stress and fatigue - When the brain is tired or we are under pressure to speak in front of someone, the process of memory retrieval slows down. - Aging - TOT experiences may occur more frequently with aging because the brain takes longer to integrate information.

The Kerala Story 2 is ready to hit the OTT platform. When and where to watch the social thriller?

The Kerala Story 2, starring Ulka Gupta, Aditi Bhatia, and Aishwarya Ojha, is now set to release online. When will The Kerala Story 2 release on OTT? After its theatrical release, The

Kerala Story 2, starring Ulka Ojha, is set to release on OTT Story 2," starring Ulka Gupta, now ready for a digital release February 27th. Produced by of Sunshine Pictures and the film faced several legal delay before reaching theaters. spiritual sequel to the 2023 film a story based on the same Kerala. However, the sequel film. When will The Kerala will be available to watch online The platform confirmed its announcement on social media. be available in Hindi, Telugu, 'The Kerala Story 2': 'The spiritual sequel of sorts to the Story.' The first film starred directed by Sudipto Sen. It won and Best Cinematography. solely on Kerala, this new film

Gupta, Aditi Bhatia, and Aishwarya platforms two months ago. "The Kerala Aditi Bhatia, and Aishwarya Ojha, is two months after its theatrical release on Vipul Amrutlal Shah under the banner directed by Kamakhya Narayan Singh, hurdles, a temporary hold, and a brief What is the film's story? It is billed as a "The Kerala Story." This film also tells theme, but its backdrop extends beyond grossed less at the box office than the first Story 2 hit the OTT platform? The film on ZEE5 and its release date is May 1. digital premiere through an The streamer also stated that the film will Tamil, Malayalam, and Kannada. About Kerala Story 2' is being described as a 2023 blockbuster film 'The Kerala Adah Sharma in the lead role and was the National Awards for Best Direction While the story of the first film was based depicts stories of forced religious

conversions in Kerala as well as other states like Rajasthan and Madhya Pradesh. The film faced protests - The controversy started with the release of the film's trailer. The trailer faced severe criticism from a section of the society; this section argued that the story of the film could incite communal tension in Kerala.

A new 8-episode OTT series, the ultimate mystery thriller, became the number one hit on Netflix as soon as it arrived; it will fill your heart with fear.

A new web series has arrived on Netflix, reaching the number one spot immediately. The story and scenes will send shivers down your spine. The new web series has become the number

one hit on Netflix. The suspense. The series What happens when becomes the cause of arrived on OTT that is episode horror-mystery Netflix. The series has since it debuted on ratings and has series even received a tells the story of five contemplate fulfilling their way. What is the revolves around an app its users. The twist using the app. This school students try to about the app, and the devastated. The web Korean drama "If Park Eun-seo, the web Mi-na, Baek Sun-ho, The series was released

8-episode series is packed with received a 7.3 rating from IMDb. the very thing that fulfills a wish death? A new web series has sure to be heart-wrenching. This 8- thriller was recently released on been a huge hit with audiences ever OTT. The series has received strong received praise from critics. The 7.3 rating from IMDb. The series children who, while having fun, their desires, but death stands in story of the web series? The story that claims to fulfill the wishes of comes when a student dies after leads to a series of deaths. Five dig deeper to find out information truth they uncover leaves them series we are talking about is the Wishes Could Kill." Directed by series stars Jeon So-young, Kang Hyun Woo-seok, and Lee Hyo-jae. on the OTT platform Netflix (If

Wishes Could Kill On Netflix) on April 24th. It quickly became the No. 1 OTT platform. It surpassed several other top-rated series to reach the No. 1 spot on the Top 10 Trending list.

Little Dua's first outing, Dhurandhar actor Ranveer Singh took his daughter to a live show.

Dhurandhar actor Ranveer Singh and Deepika Padukone's daughter Dua attended her first live musical show in Mumbai. Ranveer and Deepika's daughter Dua attended the musical

show. The "Dhurandhar 2" actor recently announced their second pregnancy. Singh took their one-and-a-half-year-old Amidst this happy period, the couple is and recently stepped out for a special life. "Dhurandhar" star Ranveer Singh was live show at the Nita Mukesh Ambani Mumbai, where the "CoComelon Sing-A- place. Ranveer Singh expressed his Ranveer expressed his joy, saying that this especially because it was Dua's first live Ranveer Singh and Deepika's fan pages, in seen talking about this experience. He said, because this is our 'Dua Baby's' first show NMACC team for bringing us such world and giving us the opportunity to lifetime." Ranveer and Deepika announced 2018 and had a beautiful wedding in Italy 2024, the couple welcomed their first child, coming soon - Last week, Deepika with Ranveer Singh. The actress broke the

expressed his joy - the couple Deepika Padukone and Ranveer daughter Dua on her first outing. thoroughly enjoying family time, occasion in their daughter Dua's seen taking little Dua to her first Cultural Centre (NMACC) in Long LIVE" event was taking happiness - After the show, moment was very special for him, show. A video is going viral on which the "Dhurandhar" actor is "This is extra special for us and I am so grateful to the experiences from around the create memories that will last a their wedding plans in October a month later. On September 8, daughter Dua. A little guest is announced her second pregnancy news by sharing a personal post

with her daughter Dua, which made the moment even more special. Deepika shared the news in a simple yet emotional way on Instagram. The post had a glimpse of her daughter Dua Singh Padukone, who was seen holding a pregnancy test. Ranveer Singh's work front- Ranveer Singh is currently enjoying his spy thriller 'Dhurandhar 2'. The film is creating a stir at the Indian box office as well as worldwide. He is joined by actors like Arjun Rampal, Sanjay Dutt, R Madhavan, Rakesh Bedi, Sara Arjun in this film.